आकाशवाणी शिमला

10.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों की पैंशन एरियर सहित की बहाल।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा–हाईकोर्ट के फैसले से हुई सरकार की किरकिरी।
- संसदीय कार्य व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा–सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर लेगी अगला निर्णय।
- राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने युवाओं से किया गौसेवा कार्य में बढ़–चढ़कर भाग लेने का आहवान।
- प्रदेश सरकार ने आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सुनीं जन समस्याएं।

हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों को एक महीने के भीतर पैंशन और एरियर जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने याचिका का निपटारा भी कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा सचिव को दिए गए निदेर्शों में अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों को एक महीने के भीतर एरियर सहित पैंशन और अन्य देय राशि जारी करने को कहा गया है। आदेशों में ये भी कहा गया है कि यदि इन पूर्व विधायकों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पैंशन और एरियर जारी नहीं किया जाता है तो विधानसभा सचिव उन्हें संबंधित राशि 6 प्रतिशत ब्याज की दर से देने के लिए जिम्मेवार होंगे।

भाजपा

इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पैंशन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए कानून को हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। जयराम ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकार की फजीहत हुई है और विधानसभा की गरिमा को भी ठेस पहुंची है।

दूसरी ओर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि अयोग्यता के आधार पर सरकार द्वारा विधायकों की पैंशन रोकना असंवैधानिक है क्योंकि दल–बदल कानून में ऐसा कोई प्रावधान नही है। राकेश जमवाल ने कहा कि संविधान में पहले से ही अयोग्यता से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि पार्टी बदलने पर विधायक अयोग्य घोषित किया जा सकता है लेकिन ये प्रावधान सिर्फ सदस्यता समाप्त करने तक सीमित है और इनमें पैंशन समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

हर्षवर्धन

इधर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार अदालत के फैसले का अध्ययन करेगी और इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में कहा कि सरकार ने दल–बदल और क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए ही पैंशन से जुड़ा नया कानून लाया है। उन्होंने कहा कि ये कानून किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग जैसी घटना प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई।

हर्षवर्धन चौहान ने ये भी कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात काफी चुनौतीपूर्ण है। इस कारण सरकार को नेताओं व अफसरों के वेतन को रोकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट का लगभग 80 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पैंशन और कर्ज लौटाने पर ही खर्च हो रहा है।

विपिन परमार

विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश सरकार के तीन वर्ष से अधिक के कार्यकाल के खिलाफ आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर जन आक्रोश रैलियों का आयोजन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा जिला के सुलह में जन आक्रोश रैली को सम्बोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने और विकास कार्यों को ठप्प करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए झूठी गारंटियां दी और अब उन्हें पूरा करना भूल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट और जनविरोधी नीतियों से त्रस्त है। विधायक डॉक्टर जनक राज ने भरमौर में जन आक्रोश रैली को सम्बोधित करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों को आम जनता के हितों के खिलाफ बताया। शिमला में आयोजित जन आक्रोश रैली को सम्बोधित करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य को बीते साढ़े तीन सालों में आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर खड़ा कर दिया है और अब अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डाला जा रहा है।

राज्यपाल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आध्यात्मिक संस्थाओं की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों के बीच भारत की सभ्यता की संस्कृति को बनाए रखने में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही हैं। राज्यपाल आज नई दिल्ली में धर्म संघ महाविद्यालय के दौरे के दौरान छात्रों को संबांधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, दया और सेवा की भावना अपनाने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि सच्ची शिक्षा ज्ञान, चरित्र और सांस्कृतिक जागरूकता के मेल में है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को गौ सेवा कार्य में बढ़चढ़ कर भाग लेने की भी अपील की और कहा कि भारतीय पंरपरा में गौ सेवा महत्वपूर्ण कार्य है।

जनता के द्वार

प्रदेश सरकार द्वारा आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में मंत्रियों और विधायकों ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनका समाधान किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला के मूरंग झूला में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं से अवगत करवाना और उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। उन्होंने 19 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया।

चन्द्र कुमार

कृषि व पशुपालन मंत्री चन्द्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आम जनता को उनके घर–द्वार पर ही सुविधाएं उपलब्ध करवाना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। चन्द्र कुमार आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जनसमस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरोटा सूरियां में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर करोड़ों रूपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 2 सौ 13 करोड़ रूपए से अधिक की सुखाहार मध्यम सिंचाई योजना तैयार की जा रही है। इससे 2 हजार एक सौ 86 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा हासिल होगी।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ही आत्मनिर्भर हिमाचल का आधार है। आज सोलन विकास खण्ड के तहत नवसृजित ग्राम पंचायत धार बखूना के शुभारम्भ के मौके पर उन्होंने कहा कि इस नई पंचायत के बनने से क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, बेहतर सड़कें, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा, निर्बाध बिजली और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

विक्रमादित्य

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जनसमस्याओं का घर–द्वार पर निपटान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की दूरदराज पंचायत निहरी में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्व लोक अदालतों सहित कई नई पहल शुरू की हैं। इससे लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार दूरदराज क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता दे रही है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में 9 पंचायतों की एक सौ 81 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया।

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश नवीन पहल के साथ आगे बढ़ रहा है और विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों सहित गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। रोहित ठाकुर आज चौपाल में अस्थायी खेल छात्रावास के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चौपाल को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। उन्होंने चौपाल में स्कूल के प्राथमिक अनुभाग कार्यालय का शिलान्यास भी किया।